SHRI MANAS RANJAN BHUNIA: Sir, I want to know, through you, from the hon. Minister: What prompted the Government and your Department with a pressing effect to disinvest ONGC, which is one of the top Navratna companies in our country? What are the reasons?

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Sir, I think the hon. Member is not adequately informed. There is no plan of disinvestment of ONGC. This is the latest information the Government have.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, it was reported in the media that 149 oilfields of the ONGC are going to be privatised. Sir, ONGC is a profit making company. Why are the oilfields being privatised? What is the logic behind that? Please explain.

श्री धर्मेंद्र प्रधान: सभापति महोदय, अगर आप अनुमति दें, तो मैं माननीय सदस्य को बाद में भी समझा सकता हूं, लेकिन अभी मैं संक्षेप में समझाता हूं।

सभापति महोदय, देश के resources के सामने दो चुनौतियां हैं- हमारे घर में सम्पत्ति है, उसकी एक कल्पना रखे रहना या उसको monetise करना। Disinvestment नहीं हो रहा है, privatization नहीं हो रहा है, एक पारदर्शी bidding process से ONGC के कुछ discovered fields को हम public domain में रख रहे हैं। भारत की विधि-व्यवस्था की अनुयायी सरकार के खज़ाने को पैसा कौन ज्यादा देगा, उत्पादन कौन ज्यादा करेगा, इन दो ही मानकों पर हम monetise कर रहे हैं। उसमें ONGC भी reinvest कर सकती है, अन्य सरकारी कंपनियां भी कर सकती हैं और टेक्नोलॉजी वाली विश्व की कोई भी कंपनी हो, वह भी कर सकती है। यही शायद हमारे देश की energy security है। हम 80 परसेंट oil requirement import करते हैं। हम import क्यों करें, हम अपने देश के resource को monetise क्यों नहीं करें, यह सरकारों की लगातार पहल रही है और हम भी इसको आगे कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 124. ...*(Interruptions)*... It is very specific. Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI K.K. RAGESH: Sir, it was not answered. ...*(Interruptions)*... I was talking about 149 oilfields, which are going to be privatised. ...*(Interruptions)*...

Data regarding employment in Groups 'A, B, C & D'

*124. PROF. MANOJ KUMAR JHA: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the data of total number of candidates who were offered Government jobs in Group A, B, C, D in various Government Departments between May 2014 to May 2019;

(b) the figures with respect to the number of sanctioned posts in Group C and D in various Government Departments and how many posts of Group C and D are lying vacant out of these; and

(c) the figures of employment growth in the unorganized sector between November 2016 to March 2018 and also the figures of employment growth in unorganized sector between June 2004 to March, 2009?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Government jobs are offered to the candidates against the vacancies arising on account of retirement, promotion, resignation, transfer, death of officers/employee, creation of new posts, etc. These vacancies are filled-up by the concerned Ministry/ Department/Organisation as per the provisions in the Recruitment Rules for the relevant posts. The data relating to this is not maintained centrally. However, 2,45,470 Government vacancies/jobs were offered to candidates through UPSC and SSC during 2014-19. Apart from these two recruiting agencies there are other agencies like Railway Recruitment Board, Institute of Banking Personnel Selection(IBPS),etc that undertake recruitment for Government vacancies/jobs.

(b) The Group D posts have been integrated (categorised) into Group C after the implementation of Sixth Central Pay Commission. There were 33,47,498 sanctioned posts, 27,73,209 number of employees in position and 5,74,289 vacant posts of Group C as on 01.03.2018 in the various Ministries/Departments of the Government. The Government has made the recruitment process of Group C and Group B (non-gazetted) easy and more transparent by removing compulsion of interview in such posts with effect from 2016.

(c) The employment in the informal sector during 2004-05 as per 61st round of NSSO was 77.5 per cent, during 2009-10 as per 66th round of NSSO was 71.1 per cent and during 2017-18 was 68.4 percent as per Periodic Labour Force Survey (PLFS) conducted by National Sample Survey Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation during 2017-18. The results of the PLFS with earlier rounds of NSS Surveys need to be understood in the context with which survey methodology and sample selection has been designed.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, is there any institutional mechanism in place to keep consolidated data of vacancies and potential recruitment, particularly, in view of unprecedented unemployment crisis?

श्री संतोष कुमार गंगवार: सर, माननीय सदस्य महोदय ने जो सवाल किया है, वह मुख्य तौर पर सरकारी नौकरी के संबंध में है। सरकारी नौकरी का एक सिस्टम सेट होता है। ए, बी और सी मामलों में पांच सालों में जो स्थान रिक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के तहत की नौकरी ऑफर की जाती है। पिछले पांच वर्षों में यूपीएससी और एसएससी के द्वारा 2,45,470 नौकरियां ऑफर की गईं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की 17 अन्य recruiting agencies, जैसे- IBPS, Railway Recruitment Board, विभिन्न मंत्रालयों की ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे हमारे मंत्रालय में EPFO और ESIC है, ये पहले से भी भर्तियां कर रहे हैं। इन सभी संस्थानों में जो recruitment हो रहा है, उसकी जानकारी हम समय-समय पर देने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त, अगर आप कोई specific जानकारी चाहते हैं, अगर आप हमको बताएंगे, तो हम उसकी सूचना आपको भेज देंगे।

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, what the hon. Minister has said was already reported and laid on the Table. My question was different. Anyway, the second supplementary question is this. There is a perceptible decline in informal sector employment. What are the plausible reasons and has the Ministry done any kind of due diligence on it?

श्री संतोष कुमार गंगवार: सर, informal sector में decline हो रहा है, ऐसी कोई सूचना नहीं है, पर जब से हमारी सरकारी आई है...**(व्यवधान)**...

प्रो. मनोज कुमार झा: ऐसा आपके डेटा में है।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: अब उनको बोलने दीजिए न, आपने सवाल पूछा है।

श्री संतोष कुमार गंगवार: हमारी सरकार जैसे ही आई है, हम इसमें और सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। दुनिया में सबको मालूम है कि भारत दुनिया की सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। दुनिया में जिस प्रकार से employment, unemployment का रेट है, उसके मुकाबले हिन्दुस्तान में यह सबसे कम है, पर हम इससे संतुष्ट नहीं है और हमारी सरकार नौकरी देने के मामले में बहुत सक्रिय है।

जहां तक formal sector की बात है, हमारा रिकॉर्ड सबकी जानकारी में है कि स्वयं EPFO और Provident Fund में पिछले तीन वर्षों में एक-एक करोड़ नई नौकरियां बढ़ी हैं जिसमें average age 28 साल की है।

SHRI P. BHATTACHARYA: Sir, the hon. Minister has said that the Government has made the recruitment process of Group C and Group B (non-gazetted) easy and more transparent by removing compulsion of interview in such posts with effect from 2016.

MR. CHAIRMAN: What is your question?

SHRI P. BHATTACHARYA: Sir, my question is very simple. After removing this interview, do you think the employment-seekers are getting any benefit or the same types of things are still happening? With regard to written examination, do you think all the complications are being removed or do they still exist?

श्री संतोष कुमार गंगवार: महोदय, इस प्रक्रिया के तहत नौकरी मिलने में एक साल का समय लग जाता है, पर ग्रुप डी में इंटरव्यू को समाप्त किया गया है, जो आदरणीय प्रधान मंत्री ने एक अच्छा कदम उठाया है और जैसा मैंने कहा कि रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया पूरी होने में एक वर्ष का समय लग जाता है। हर साल 10-12 परसेंट सीट्स खाली हो रही हैं। हम उनको पूरा करने की दिशा में सक्रिय हैं। ग्रुप डी में इंटरव्यू न होने से हमें लाभ हो रहा है, जल्दी रिक्रूटमेंट हो रहा है, अगर आपकी कोई स्पेसिफ़िक शिकायत है तो आप हमें बताएं, हम उसका तुरंत निस्तारण करेंगे।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: महोदय, अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर, सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला क्षेत्र है। हमें जो जवाब मिला है, उसमें लगातार नौकरियों का प्रतिशत गिर रहा है। वर्ष 2009-10 में 71.1 प्रतिशत था और वर्ष 2017-18 में 68.4 प्रतिशत है। माननीय मंत्री जी से मेरा बहुत ही स्पेसिफ़िक प्रश्न है कि यह तो बहुत सारे सेक्टर्स में involved है, बेसिकली एग्रो प्रोसेसिंग में, जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है।

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: महोदय, एग्रीकल्चर में अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर का जो परसेंटेज है, क्या आपके पास उसको planned way में बढ़ाने का कोई कार्यक्रम है? यदि है, तो बता दीजिए।

श्री संतोष कुमार गंगवार: महोदय, असंगठित क्षेत्र में रोज़गार देने के लिए सरकार बहुत सक्रिय और प्रगतिशील है। हम जानते हैं कि देश के अंदर असंगठित क्षेत्र में करीब 40 करोड़ ऐसे लोग हैं, जो कार्य करते हैं और सरकार ने उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि जब वे 60 वर्ष के हो जाएंगे, तब उनको 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उस कार्यक्रम के तहत चाहे रोड बनाने का काम हो...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: एग्रो के बारे में बताइए।

श्री संतोष कुमार गंगवार: महोदय, हम जिस तरह का काम कर रहे हैं, उसका हमें अच्छा लाभ मिल रहा है। मैं इतना कह सकता हूं कि मैं अनऑर्गनाइज्ड क्षेत्र की पूरी डिटेल लिखित में दे दूंगा कि किन-किन क्षेत्रों में काम हो रहा है, एक रिकॉर्ड पैमाने पर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो रहा है। इन सबके माध्यम से रोज़गार के अवसर सृजित हो रहे हैं।

श्री सभापति: आप एग्रो के संबंध में भी जानकारी इकट्ठी करके भेज दीजिएगा। Shri Ahamed Hassan.

SHRI AHAMED HASSAN: Sir, I would like to know from the hon. Minister the unemployment rate in the country recorded in the last year and the details thereof. Second thing I want to know...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No second thing. Only one thing. Do you want to say something?

श्री संतोष कुमार गंगवार: महोदय, unemployment rate, जो विश्व के पैमाने पर होता है, दुनिया के देशों में सबसे कम हमारे देश में है, यह ILO की रिपोर्ट है। मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में रिपोर्ट लाऊंगा चुनाव से पहले लोगों ने जो आंकड़े दिए थे, वे सत्य नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि LIO के अनुसार भारत में unemployment rate 3.5 परसेंट है, चाइना में 4.7 परसेंट है, Asia-Pacific में 4.2 परसेंट है। मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान की स्थिति इन सबसे बेहतर है, पर हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी, इसमें और सुधार करने की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में रोज़गार की समस्या है, पर समस्या यह है कि अब व्यक्ति स्थायी नौकरी चाहता है, सरकारी नौकरी चाहता है और पुराने रोज़गार को बताने का काम नहीं करता है।

MR. CHAIRMAN: Now, Q.No. 125.

Fire at coaching centre in Gujarat

*125. SHRI RAJKUMAR DHOOT: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that appropriate ladders could have saved the lives of students of coaching centre in Surat, Gujarat devastated by fire and fire brigade had no ladders to save the students trapped on fourth floor of the building;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government proposes to ensure that fire brigades throughout the country do have all the necessary fire fighting equipments including ladders in position; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NITYANAND RAI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) As per information furnished by Government of Gujarat, the Fire Brigade staff promptly reached the fire incident site and saved 15 lives. However, due to very short response time available, all persons trapped on 4th floor could not be saved.